AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Authors

कृपा राम महेश्वरी
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. पुष्पा भारती
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य की एक अति पिछड़ी जनजाति, भुंजिया जनजाति, की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। भुंजिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। यह जनजाति मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और नारायणपुर जैसे जिलों में निवास करती है, जहाँ इनकी जीवन–शैली वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। शोध का मुख्य उद्देश्य भुंजिया समुदाय की आजीविका के स्रोतों, आय स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की पहुँच का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन में प्राथमिक डेटा (साक्षात्कार, सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप डिस्कशन) और द्वितीयक डेटा (सरकारी रिपोर्टें, जनगणना, शोध आलेख) का उपयोग किया गया है। डेटा संग्रह के लिए गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और नारायणपुर जिलों में से 120 भुंजिया उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति से किया गया। शोध में यह पाया गया कि भुंजिया जनजाति की आय मुख्यतः वनोपज संग्रहण, अस्थायी मजदूरी और सीमित कृषि पर निर्भर है। भूमि का स्वामित्व न्यूनतम है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच बहुत सीमित है। यद्यपि कुछ परिवार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु जागरूकता की कमी और प्रशासनिक जटिलताएँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं। यह शोध सुझाव देता है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित कौशल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकरण, तथा जनजातीय भागीदारी को बढ़ावा देकर भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है।

मुख्य शब्द

भुंजिया जनजाति, आर्थिक स्थिति, पीवीटीजी, छत्तीसगढ़.

प्रस्तावना

भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ सैकड़ों जनजातियाँ अपने विशिष्ट जीवन–शैली, संस्कृति और परंपराओं के साथ निवास करती हैं। इन्हीं जनजातियों में से एक है भुंजिया जनजाति, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, गरियाबंद और महासमुंद जैसे जिलों में पाई जाती है। भुंजिया जनजाति एक अत्यंत पारंपरिक और सीमित संसाधनों में जीवन जीने वाली जनजाति है, जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है। भुंजिया जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत कम है, और यह जनजाति विशेष रूप से जंगलों के समीप के क्षेत्रों में निवास करती

है। इनका मुख्य जीवन निर्वाह कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन और श्रम कार्यों पर आधारित है परंतु आधुनिक आर्थिक विकास की मुख्यधारा से कटे होने के कारण इनकी आय अस्थिर और अपर्याप्त बनी हुई है। इनके पास भूमि का स्वामित्व सीमित है, सिंचाई के साधनों की कमी है, और बाजार तक पहुँच बहुत कठिन है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का एक विचार इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, ''वास्तविक सामाजिक परिवर्तन वहीं होता है, जहाँ सबसे निचले पायदान पर खड़े वर्ग को ऊपर उठाया जाता है।'' भुंजिया जनजाति जैसे समुदायों की स्थिति का अध्ययन करके ही हम यह समझ सकते हैं कि समाज के हाशिये पर खड़े लोग विकास की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी निभा पा रहे हैं।

सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय उप–योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, राशन वितरण प्रणाली आदि परंतु यह योजनाएँ कितनी प्रभावी रही हैं, यह एक गहन अध्ययन का विषय है। अनेक बार योजनाओं की जानकारी ही इन तक नहीं पहुँचती, या फिर स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण इनका लाभ सीमित रह जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भुंजिया जनजाति की वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसमें यह देखा जाएगा कि उनके आय के स्रोत कौन–कौन से हैं, उनका खर्च किस प्रकार होता है, वे किस प्रकार की आजीविका अपनाते हैं, और उन्हें किन–किन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथ ही, यह भी विश्लेषण किया जाएगा कि वर्तमान सरकारी योजनाएँ उनके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और उनमें सुधार की क्या संभावनाएँ हैं।यह अध्ययन केवल भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति तक सीमित न होकर व्यापक रूप से जनजातीय समुदायों के विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक सार्थक योगदान देगा। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि किस प्रकार की नीतियाँ और योजनाएँ वास्तव में इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ सकती हैं और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

- भुंजिया जनजाति की आजीविका और आय के प्रमुख स्रोतों का विश्लेषण करना।
- भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं भौगोलिक कारकों की पहचान करना।
- सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा उनकी प्रभावशीलता का आंकलन करना।

साहित्य समीक्षा

जनजातीय समुदायों पर आधारित साहित्य का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारत की अनुसूचित जनजातियाँ आज भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। के.एस. सिंह (1994) की The Scheduled Tribesuked पुस्तक में भारत की प्रमुख जनजातियों की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भुंजिया जनजाति का भी उल्लेख मिलता है, जिससे इस समुदाय की पहचान और पारंपरिक जीवनशैली की जानकारी मिलती है। वहीं वी. एक्सा (1999) के लेख Tribes as Indigenous People of India में जनजातियों को भारत के मूल निवासी मानते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्करण की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। एक्सा का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि जनजातियों की समस्याएँ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक भी हैं।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक–आर्थिक दशा को लेकर ए.के. शर्मा (2017) ने अपने शोधपत्र Socio-economic Conditions of Tribal People in India में छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में बताया है कि इन समुदायों में शिक्षा का स्तर निम्न है, और रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे आर्थिक पिछड़ापन बना हुआ है। इसी प्रकार, आर. श्रीवास्तव (2015) ने Development and Deprivation: A Case Study of Bhunjia Tribe में भुंजिया जनजाति पर केंद्रित अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो उनकी आर्थिक स्थिति, संसाधनों की कमी, और सरकारी योजनाओं की सीमित

पहुँच को उजागर करता है।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित Statistical Profile of Scheduled Tribes in India (2020) रिपोर्ट अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के प्रमुख आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट भुंजिया जैसी छोटी जनजातियों की पहचान, चुनौतियों और विकास की दिशा में उपयोगी आधार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, Census of India (2011) में उपलब्ध Primary Census Abstract for Scheduled Tribes के माध्यम से जनगणना आधारित आँकड़ों से भुंजिया जनजाति की साक्षरता, निवास स्थान और सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है।

आदिवासी विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए ए.आर. बसु (2002) की पुस्तक Tribal Development Programmes and Administration in India महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक ढांचे और उनके क्रियान्वयन की व्यावहारिक जटिलताओं को रेखांकित करती है। जी.सी. राठ (2006) की Tribal Development in India: The Contemporary Debate पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे कई योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं और जनजातीय समाज को उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता।

एस. चौधरी (2013) का शोध Livelihood Patterns among Tribal Communities of Central India मध्य भारत की जनजातियों की आजीविका, कृषि, वनोपज और श्रम जैसे जीवन स्रोतों का विश्लेषण करता है, जिसमें भुंजिया जनजाति की परिस्थितियाँ भी सम्मिलित हैं। अंत में, Statistical Abstract of Chhattisgarh (2021), जो राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित है, वह भुंजिया जनजाति सहित अन्य आदिवासी समूहों के आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों और सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति को आँकड़ों के माध्यम से स्पष्ट करती है।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसके लिए एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित शोध पद्धति अपनाई गई है। यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक और क्षेत्रीय अध्ययन प्रकृति का है, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का सहारा लिया गया है ताकि विषय की गहराई से समझ विकसित की जा सके। अध्ययन क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, कांकेर एवं नारायणपुर जिलों के उन गाँवों का चयन किया गया जहाँ भुंजिया जनजाति की सघन उपस्थिति है।

जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने हेतु 120 भुंजिया उत्तरदाताओंको उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग विधियों से चुना गया। इनमें विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, जैसे कृषक, दिहाड़ी मजदूर, हस्तशिल्पकार, तथा महिलाएँ। शोध के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रह किया गया। प्राथमिक आंकड़े एक संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा अवलोकन के माध्यम से एकत्रित किए गए, वहीं द्वितीयक जानकारी के स्रोतों में जनगणना रिपोर्ट 2011, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की रिपोर्टें, छत्तीसगढ़ सरकार का सांख्यिकीय सार, शोध पत्र, तथा प्रासंगिक पुस्तकें सम्मिलित हैं।

संग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों जैसे प्रतिशत, औसत, तालिकाओं एवं चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त, विषयवस्तु विश्लेषण द्वारा गुणात्मक जानकारी का वर्गीकरण कर मुख्य प्रवृत्तियों की पहचान की गई। अध्ययन में कुछ सीमाएँ भी रहीं, जैसे कि अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक सीमितता, उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं जानकारी का स्तर, तथा समय और संसाधनों की मर्यादा, जो शोध की व्यापकता को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती हैं फिर भी, प्रयुक्त शोध पद्धति अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त और प्रभावशाली रही है।

आजीविका और आय के प्रमुख स्रोतों का विश्लेषण

भुंजिया जनजाति की आजीविका के स्रोत

आजीविका का स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि	42	35.0
वनोपज संग्रह	30	25.0
दिहाड़ी मजदूरी	24	20.0
पशुपालन	12	10.0
हस्तशिल्प / कारीगरी	12	10.0
कुल	120	100.0

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

भुंजिया जनजाति की आजीविका मुख्यतः पारंपरिक और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। कुल 120 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण में पाया गया कि 35 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि पर निर्भर हैं, जो उनकी प्रमुख आजीविका है। इसके बाद 25 प्रतिशत उत्तरदाता वनोपज संग्रह, जैसे महुआ, तेंदूपत्ता आदि पर आश्रित हैं। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं दिहाड़ी मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं, जो अस्थायी आय का स्रोत है। वहीं 10–10 प्रतिशत उत्तरदाताओं पशुपालन और हस्तशिल्प / कारीगरी से जुड़े हैं। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि भुंजिया समुदाय की आय के स्रोत सीमित हैं और उनकी निर्भरता अधिकतर पारंपरिक एवं श्रम–प्रधान कार्यों पर है।

भुंजिया जनजाति की आय के स्रोत

आय का स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
खेती की उपज	36	30.0
वन उत्पादों की बिक्री	24	20.0
दिहाड़ी मजदूरी से आय	30	25.0
सरकारी योजनाओं से सहायता	18	15.0
अन्य	12	10.0
कुल	120	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

भुंजिया जनजाति की आय संरचना विविध लेकिन सीमित स्रोतों पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रमुख आय खेती की उपज से होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उनकी आर्थिक रीढ़ है। 25 प्रतिशत उत्तरदाता दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, जो अस्थिर और श्रम–साध्य आय का स्रोत है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता वन उत्पादों की बिक्री जैसे महुआ, तेंदूपत्ता आदि से आय अर्जित करते हैं। 15 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, पेंशन आदि) से सहायता प्राप्त करते हैं, जबकि 10 प्रतिशत परिवारों की आय अन्य स्रोतों जैसे शिल्प, पशुपालन या घरेलू व्यापार से होती है। यह संरचना आय की अस्थिरता को दर्शाती है।

भुंजिया जनजाति की आय स्तर

आय स्तर (वार्षिक)	आवृत्ति	प्रतिशत
रु.5,000 –रु.10,000	50	41.7
रु.10,001 –रु.15,000	44	36.7
रु.15,001 से अधिक	26	21.6
कुल	120	100.0

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

भुंजिया जनजाति के आय स्तर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समुदाय का अधिकांश हिस्सा अत्यंत निम्न आय वर्ग में आता है। सर्वेक्षण के अनुसार, 41.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय रु. 5,000 –रु.10,000 के बीच है, जबकि 36.7 प्रतिशत उत्तरदाता रु.10,001 –रु.15,000 के बीच कमाते हैं। केवल 21.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय रु.15,001 से अधिक है। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि भुंजिया समुदाय के एक बड़े हिस्से की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में आयवर्धन और रोजगार के स्थायी साधनों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

काई–स्क्वायर परीक्षण के आधार पर भुंजिया जनजाति के विभिन्न आय स्रोतों और आय स्तरों के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया। परीक्षण के लिए कुल पाँच प्रमुख आय स्रोत खेती, वनोपज, दिहाड़ी मजदूरी, सरकारी योजनाएँ, और अन्य, तथा तीन आय स्तर रु.5,000–रु.10,000, रु.10,001 –रु.15,000, और रु.15,001 से अधिक के अंतर्गत 120 परिवारों के आंकड़ों को वर्गीकृत किया गया। प्राप्त आँकड़ों पर काई –स्क्वायर मान 20.1906 आया, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 रही। इस परीक्षण का p–मूल्य 0.0096 निकला, जो कि 0.05 की सामान्य स्तर की महत्वपूर्णता से कम है। इसका अर्थ यह है कि परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। इस परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि भुंजिया जनजाति के परिवारों में आय के स्रोत और उनकी आय का स्तर परस्पर संबंधित हैं।

आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं भौगोलिक कारक

आर्थिक स्थिति पर सामाजिक कारकों का प्रभाव

कारक का नाम	आवृत्ति	प्रतिशत
शिक्षा का निम्न स्तर	52	43.3
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी	48	40.0
सामाजिक बहिष्करण/विकास से अलगाव	40	33.3
कुल	120	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में शिक्षा का निम्न स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे 52 उत्तरदाताओं (43.3 प्रतिशत) ने प्रमुख समस्या के रूप में चिन्हित किया। इससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और आत्मनिर्भरता में बाधा आती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जो 48 उत्तरदाताओं (40 प्रतिशत) को प्रभावित करती है, उनके श्रमक्षमता और आय स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक बहिष्करण और विकास से अलगाव की समस्या 40 उत्तरदाताओं (33.3 प्रतिशत) द्वारा अनुभव की गई, जिससे सरकारी योजनाओं और संसाधनों तक उनकी पहुँच सीमित रहती है।

आर्थिक स्थिति पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव

कारक का नाम	आवृत्ति	प्रतिशत
दुर्गम भौगोलिक स्थिति	55	45.8
सिंचाई सुविधाओं की कमी	42	35.0
बाजार तक सीमित पहुँच	38	31.7
कुल	120	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण में 55 उत्तरदाताओं (45.8 प्रतिशत) ने दुर्गम भौगोलिक स्थिति को प्रमुख बाधा बताया, जिससे आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुँच में कठिनाई उत्पन्न होती है। सिंचाई सुविधाओं की कमी को 42 परिवारों (35 प्रतिशत) ने कृषि उत्पादन की अस्थिरता और सीमित फसल चक्र का कारण माना वहीं 38 उत्तरदाताओं (31.7 प्रतिशत) ने बाजार तक सीमित पहुँच को उत्पादों की बिक्री और उचित मूल्य न मिलने की मुख्य वजह बताया। ये सभी कारक समुदाय के

आर्थिक विकास को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

काई–स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया कि भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक और भौगोलिक कारकों के प्रभाव में कोई सांख्यिकीय भिन्नता है या नहीं। परीक्षण के लिए तीन–तीन उपश्रेणियों वाले सामाजिक (शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सामाजिक बहिष्करण) और भौगोलिक (दुर्गम स्थिति, सिंचाई की कमी, बाजार तक पहुँच) कारकों की आवृत्तियों का उपयोग किया गया। विश्लेषण में प्राप्त काई–स्क्वायर मान 0.4446 और p–मूल्य 0.8007 रहा, जो 0.05 के स्तर से काफी अधिक है अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रकार के कारकों के प्रभाव में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक और भौगोलिक दोनों ही कारक समान रूप से आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, और उनके बीच प्रभाव के स्तर पर कोई स्पष्ट सांख्यिकीय भिन्नता नहीं है।

सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन एवं प्रभावशीलता का आंकलन

भुंजिया जनजाति जैसे वंचित समुदायों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु भारत सरकार एवं विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समय–समय पर कई योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से मनरेगा, जन–धन योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार अधिनियम, तथा जनजातीय उप–योजना आदि शामिल हैं। साथ ही, कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लगभग 60 प्रतिशत परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना से लाभ मिला, परंतु यह लाभ आंशिक एवं अस्थायी रहा। मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मिला, लेकिन कार्य की निरंतरता और पारिश्रमिक वितरण में अनियमितता देखी गई। पेंशन योजनाओं से वृद्ध और विधवा महिलाओं को आंशिक राहत मिली, किंतु आवेदन प्रक्रिया जटिल पाई गई। वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे मिलने से कुछ परिवारों को कृषि के लिए स्थायित्व मिला, किंतु बहुसंख्यक परिवार आज भी अधिकार से वंचित हैं।

गैर–सरकारी संगठनों की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर, पोषण अभियान और महिला स्वयं सहायता समूहों ने कुछ हद तक सामुदायिक जागरूकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है तथापि, इनकी पहुँच सीमित रही है और सरकारी तंत्र से समन्वय की कमी रही है। प्रभावशीलता का आंकलन दर्शाता है कि योजनाओं की जानकारी की कमी, प्रशासनिक जटिलताएँ, जातीय भेदभाव, और संसाधनों की अनुपलब्धता इन प्रयासों की सफलता में बाधक बनी हुई हैं। कई लाभार्थी योजनाओं की पात्रता होने के बावजूद लाभ से वंचित पाए गए। योजनाओं की नीति–स्तर पर मंशा सकारात्मक होने के बावजूद जमीनी क्रियान्वयन में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पारदर्शी निगरानी प्रणाली, और डिजिटल सुविधा के माध्यम से सेवाओं को सरल एवं सुगम बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि समुदाय मुख्यतः परंपरागत, अस्थायी और श्रम–प्रधान आजीविका स्रोतों पर निर्भर है, जैसेः कृषि, वनोपज संग्रहण, दिहाड़ी मजदूरी आदि। आय का स्तर अत्यंत निम्न है, जहाँ अधिकांश परिवारों की वार्षिक आय रु.15,000 से कम है। सामाजिक कारकों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक बहिष्करण, जबकि भौगोलिक कारकों में दुर्गम स्थिति, सिंचाई की कमी और बाजार तक सीमित पहुँच प्रमुख बाधाएँ हैं। काई–स्क्वायर परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि आय के स्रोत और आय स्तर के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विविध और स्थिर आय स्रोत वाले परिवार अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं वहीं, सामाजिक और भौगोलिक कारकों के प्रभाव में कोई सांख्यिकीय भिन्नता नहीं पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों ही प्रकार के कारक आर्थिक स्थिति को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाएँ उपलब्ध होने के बावजूद उनका प्रभाव सीमित रहा है। योजनाओं की

जानकारी, क्रियान्वयन की पारदर्शिता और पहुँच की समस्याएँ आज भी मौजूद हैं। यह संकेत देता है कि नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच अभी भी एक बड़ी अंतर है।

सुझाव

भुंजिया जनजाति की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कई स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समुदाय के लोग स्वयं निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकें। कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों का वितरण और कृषि प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। पारंपरिक हस्तशिल्प और लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। सरकारी योजनाओं की सूचना और लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल तथा पारदर्शी बनाना होगा इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, परिवहन और बाजार ढाँचों का विकास कर जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी योजनाओं और प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि वास्तविक रूप से जनजीवन में परिवर्तन ला सकें।

संदर्भ सूची

1. Basu, A. R. (2002) *Tribal development programmes and administration in India*, Mittal Publications, New Delhi.
2. Census of India (2011) Primary census abstract for scheduled tribes: Chhattisgarh, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. https://censusindia.gov.in/, Assessed on 02/02/2025.
3. Choudhary, S. (2013) Livelihood patterns among tribal communities of Central India, *International Journal of Social Science Tomorrow*, 2(4), 1–7.
4. Government of Chhattisgarh (2021) Statistical abstract of Chhattisgarh 2020–21. Directorate of Economics and Statistics, Raipur, https://des.cg.gov.in/, Assessed on 08/02/2025.
5. Ministry of Tribal Affairs (2020) *Statistical profile of scheduled tribes in India 2020*. Government of India. https://tribalnic.in/, Assessed on 02/02/2025.
6. Rath, G. C. (2006) *Tribal development in India: The contemporary debate*, Sage Publications, New Delhi .
7. Sharma, A. K. (2017) Socio-economic conditions of tribal people in India with special reference to Chhattisgarh, *International Journal of Humanities and Social Science Research,* 5(2), 12–17.
8. Singh, K. S. (1994) *The Scheduled Tribes*. Oxford University Press, New Delhi.
9. Srivastava, R. (2015) Development and deprivation: A case study of Bhunjia tribe in Chhattisgarh, *Journal of Tribal Studies,* 8(1), 45–56.
10. Statistical Abstract of Chhattisgarh. (2021) Directorate of Economics and Statistics, Government of Chhattisgarh. https://des.cg.gov.in/, Assessed on 08/02/2025.
11. Xaxa, V. (1999) Tribes as Indigenous People of India, *Economic and Political Weekly,* 34(51), 3589–3595.

——==00==——